जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

13 फरवरी, 2025

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अर्थशास्त्र विभाग ने केंद्रीय बजट 2025-26 पर पैनल चर्चा का आयोजन किया

नई दिल्ली : जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अर्थशास्त्र विभाग के सब्जेक्ट असोशिएशन ने 10 फरवरी, 2025 को विभाग के सम्मेलन कक्ष में केंद्रीय बजट 2025-26 पर पैनल चर्चा का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत विभागाध्यक्ष प्रो. अशेरेफ इलियान के उद्घाटन भाषण से हुई जिन्होंने यह बताया कि बजट केवल संख्याएं नहीं हैं अपितु वे सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। इसलिए बजट का विस्तृत विश्लेषण जरूरी है। उन्होंने केंद्रीय बजट 2025-26 के सकारात्मक पहलुओं पर रोशनी डाली । कार्यक्रम के प्रतिष्ठित पैनलिस्ट थे: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आर्थिक अध्ययन और योजना केंद्र के पूर्व प्रोफेसर प्रो. अरुण कुमार और जेएनयू के एसएसएस के पूर्व डीन प्रो. अमिताभ कुंडू। सत्र का संचालन जामिया के अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद जकारिया सिद्दीकी ने किया।

इस वर्ष के बजट के लिए प्रो. अरुण कुमार ने व्यापक आर्थिक संदर्भ प्रस्तुत किया। उन्होंने यह रेखांकित किया कि आर्थिक विकास धीमा हो गया है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और असमानता की वृद्धि अनियंत्रित बनी हुई है। उनके विचार में इस वर्ष का बजट बुनियादी ढांचे पर व्यय उन्मुख विकास रणनीति को अपनाने की प्रवृत्ति को जारी रखता है जो बढ़ती असमानता से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है और जो भारत में एक प्रमुख चिंता का विषय है। इसके अतिरिक्त यह रणनीति इस देश की बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की गुंजाइश को सीमित करती है। उन्होंने अनौपचारिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर रोशनी डाली क्योंकि यह भारत में गैर-कृषि कार्यबल के 75% को रोजगार प्रदान करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए रोजगार गहन क्षेत्र है।

प्रो. अमिताभ कुंडू ने भारतीय बजट में सामाजिक रूप से वंचित समुदायों की उपेक्षा की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोशनी डाली । सामान्य सामाजिक क्षेत्र के खर्च को न केवल प्रतिबंधित किया गया है अपितु अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट में भी समय के साथ महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है जबकि राष्ट्रीय औसत जैसे शैक्षिक और स्वास्थ्य परिणामों की तुलना में अल्पसंख्यकों की सामाजिक उपलब्धियों में बहुत कम उपलब्धि है। बजट में इस उपेक्षा के फलस्वरूप माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शैक्षणिक संस्थानों

में मुसलमानों के नामांकन में लगातार कमी आई है। यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017-18 में उच्च शिक्षा में नामांकन को 26.3% से बढ़ाकर 2035 में 50% करना चाहती है। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र और अल्पसंख्यकों खास तौर से मुसलमानों के लिए खर्च बढ़ाने की वकालत की।

पैनल वक्ताओं द्वारा की गई चर्चा का सारांश डॉ. ज़कारिया सिद्दीकी ने प्रस्तुत किया और मानव विकास आधारित विकास नीतियों पर खर्च को केंद्रित करके भारत में मानव विकास, बढ़ती बेरोजगारी और अभूतपूर्व असमानता में महत्वपूर्ण पिछड़ेपन के मुद्दे का मुकाबला करने वाले विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर रोशनी डाली ।

इस कार्यक्रम में छात्रों, शोधार्थियों और विभाग के संकाय सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का समापन जामिया के अर्थशास्त्र विभाग के छात्र सलाहकार डॉ. वसीम अकरम के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. वसीम अकरम और डॉ. मो. काशिफ खान ने किया। सुश्री सहाना अरक्कल और अक्षत इस कार्यक्रम की छात्र समन्वयक थीं।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया